Sr. No.	Announcement Para/Description (Year 2023-24)
1	11.02.02 (2023-2024) 10/02/2023 परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ विभागों की योजनाओं में भी identification सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जायेगा।
2	18.01.0 (2023-2024) 10/02/2023 iStart Fund के माध्यम से Startups को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली matching share की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा।
3	19.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 प्रदेश में युवाओं को अपना Startups स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपये की लागत से- I. ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों/ महाविद्यालयों में iStart लॉन्चपैड नेस्ट की स्थापना और संचालन किया जायेगा। II. Rajiv Gandhi Innovations Challenge के अन्तर्गत प्रथम award की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के साथ ही 35 करोड़ रुपये राशि के कुल 100 पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित। III. जनजाति क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में Incubation and Innovation Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4	104.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 शहरी विकास को नए आयाम तक ले जाने एवं शहरों को 'Smart' बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु '3D City' परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित '3D City' परियोजना की घोषणा। इसके लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
5	141.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज Pioneer के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में सम्भवतः पहली बार पात्र व्यक्ति / परिवारों को बिना आवेदन किये ही घर बैठे auto benefits व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके. इसके लिए जन आधार data base का उपयोग करते हुए Information Technology. Artificial Intelligence व Machine Learning आधारित Real Time Auto Service Delivery System-SWATAH (स्वतः) लागू किये जाने की घोषणा। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं स्वतः उपलब्ध हो जायेंगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना, NFSA पात्रता व आयु के आधार पर स्वतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शालादर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति / पालनहार स्वतः उपलब्ध होना।
6	142.01.0 (2023-2024) 10/02/2023 IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5 प्रतिशत भाग cyber security के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। यह निर्णय देश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
7	142.02.0 (2023-2024) 10/02/2023 सरकारी Land Records, Health Records, e- Coupons में भी किसी प्रकार के manipulations की रोकथाम के लिए इन रिकाड्र्स को Block Chain Technology द्वारा सुरक्षित संधारित किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

8	142.03.0 (2023-2024) 10/02/2023 जयपुर में Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance स्थापित किया जायेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
9	143.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ कराने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाये। सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में e-office प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में, विभागों / PSUs / बोर्ड / निगम कार्यालयों में process re-engineering करते हुए files पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मेसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसैस ऑटोमेशन, Artificial Intelligence आदि नवीनतम तकनीक आधारित RajKaj 2.0 विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
10	144.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 सुशासन हेतु यह भी आवश्यक है कि नीति निर्माण evidence based हो, उसमें behavioural science का उपयोग किया जाये तथा सरकारी योजनाओं का concurrent evaluation हो, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में real time में ही सुधार किया जा सके। इसके लिए Integrated Data Analytics System 'PARAM' विकसित किया जायेगा। साथ ही, समस्त Data के storage हेतु Centralised Data Lake बनाया जायेगा। इन पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
11	145.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 शहरी नियोजन Forest Surveillance, आपदा प्रबन्धन, कृषि, पर्यटन, खान एवं भूविज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार ड्रोन मय पायलट उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।
12	146.01.0 (2023-2024) 10/02/2023 आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र खोले जायेंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाना प्रस्तावित है।
13	199.05.0 (2023-2024) 10/02/2023 स्टार्ट-अप से बिना टेंडर उपापन (Single Source Procurement) की वर्तमान 15 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा।
14	277.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 विद्यार्थियों एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में iStart Innovation School Hub की स्थापना की जायेगी।
15	337.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 योजनाओं की प्रभावी मा ॅनिटरिंग के लिए एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म 'Raj Dhara' का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न विभागों हेतु सेटेलाइट इमेजरी की आवश्यकताओं के अनुरूप राजधारा प्लेटफॉर्म पर Time Series High Resolution Satellite Imagery Repository की स्थापना की जायेगी एवं इसके विश्लेषण हेतु High-end Lab की भी स्थापना की जायेगी, जिससे राज्य के विकास एवं आवश्यकताओं की प्रभावी समीक्षा की जा सकेगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।